>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Export-Import Bank of India (Amendment) Bill, 2011 (Bill Passed).

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Sir, on behalf of my senior colleague, Shri Pranab Mukherjee, the Finance Minister, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Export-import Bank of India Act, 1981, be taken into consideration. "

Sir, the Export-Import Bank of India (Amendment) Bill, 2011 was introduced in the Lok Sabha on 8th December, 2011. The Exim Bank was set up by an Act of Parliament in 1981 for providing financial assistance to exporters and importers and for functioning as the principal financial institution for coordinating the working of institutions engaged in financing export and import of goods and services with a view to promoting the country's international trade.

The basic objective of Export-Import Bank of India (Amendment) Bill, 2011 is to carry out the amendments in the Export-Import Bank of India Act, 1981 to increase the authorized capital of the Exim Bank from Rs.2,000 crore to Rs.10,000 crore with a provision empowering the Government of India to increase the authorized capital further that it may deem necessary from time to time through notification and to make a provision for appointment of two whole time Directors other than the Chairman and the Managing Director. The paid up capital of the bank has reached the level of its authorized capital of Rs.2,000 crore. To enable the Exim Bank to raise fresh borrowings to meet requirements of growing business, it has become necessary to increase its authorized capital and also to strengthen top management with induction of two whole time Directors at par with similar size public sector banks.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Export-import Bank of India Act, 1981, be taken into consideration. "

Now, Shri Balkrishna Shukla to speak. Please confine to time.

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला (वडोदरा): सभापति महोदय, मैं आपका आभार मानता हूं। यह दो हजार करोड़ से दस हजार करोड़ रुपये तक जाते हैं और आप कहते हैं कि समय में कनफाइन कीजिए। अगर आप कहते हैं, तो मैं नहीं बोलता हूं। अभी तो मैंने बोलना भी शुरू नहीं किया और आप कह रहे हैं कि टाइम पकड़ कर चलें। यह दो हजार करोड़ रुपये से दस हजार करोड़ रुपये यानी पांच सौ फीसदी बढ़ रहा है। ...(व्यवधान) आप मुझे बता दीजिए कि मैं कितना बोलूं। अगर एक मिनट बोलना है तो मैं भारत माता की जय बोलकर बैठ जाता हूं। अभी तक मैंने अपनी बात शुरू भी नहीं की है। ...(व्यवधान) ऐसे थोड़े ही चलता है।

MR. CHAIRMAN: Do not waste your time. I will ring the bell. You have already wasted one minute.

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला : मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। आप जो बोलेंगे, मैं वही बोलूंगा। ...(व्यवधान) लोक सभा में यह बिल सातवीं बार संशोधन के लिए आया है। जब इस बिल का मैं थोड़ा अभ्यास कर रहा था, तो मुझे मन्ना डे साहब की फिल्म एक फूल दो माली के गाने की एक पंक्ति याद आयी -- तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीपक कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राजदुलारा। जो मंत्री महोदय ने बताया है कि 1981 में जब यह संशोधन आया और फिर 1982 में बैंक शुरू हुआ। मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के एक व्यक्ति इसके आर्थिक सलाहकार बनाए गए, जो कि बैंक आफ बड़ौदा के चेयरमैन थे। उनके हाथ में भारत सरकार ने यह बागडोर सौंपी। मंत्री जी द्वारा जो ऑब्जेक्टिव्ज़ बताए गए, उनमें दो बाकी रह गए। To promote international trade into an Act on business principle with due regard to public interest. आप देखिए इतने दिनों के बाद छः बार संशोधन हो जाने के बाद आज एकाएक 2,000 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए पर हम आ रहे हैं तो आज की तारीख में भारत का फारेन ट्रेड कितना है? क्या हमारी परफार्मेंस है? सन् 2008-2009 में हमारा एक्सपोर्ट 28.90 प्रतिशत था। सन् 2009-2010 में वह .57 प्रतिशत हुआ। जो इम्पोर्ट था, वह 2008-2009 में 35.77 प्रतिशत था, वह पिछले साल निगेटिव यानि माइनस 78 प्रतिशत हुआ। रिपोर्ट में लिखा गया है कि negative growth rate of import for first time in more than two decades. आज हम जो इस राजदुलारी की बात कर रहे हैं, इसमें चंद बातों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। हमारे बिजनेस की मेन लाइंस क्या हैं, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग है, फाइनेंस टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं और ओवरसीज इंवैस्टमेंट फाइनेंस है तथा लाइंस आफ क्रेडिट है। इसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यह है कि पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए यह कर रहे हैं। यह जो ओवरसीज इंवैस्टमेंट फाइनेंस होता है, वह प्रदेश में जाइंटवेंचर होता है और कभी-कभी 100 प्रतिशत भी हो जाता है। अभी ग्लोबल रिसैशन चल रहा है, हालांकि हम एफडीआई की बात करते हैं और चाहते हैं कि परदेसी लोग, प्राइवेट कम्पनीज यहां आएं और अपना बिजनेस डवलप करें। ग्लोबली जीडीपी देखी जाए, जो अतिपूगति देश हैं, उनके साथ अपनी तुलना करें कि हम कहां हैं तो हमारे यहां 6.9 प्रतिशत है। इसकी तुलना में जो बाकी देश हैं, जैसे अमेरिका है, उसका 2.9 प्रतिशत है, यूरोप का 1.8 प्रतिशत है, जर्मनी का 3.5 प्रतिशत है, फ्रांस का 1.4 प्रतिशत है, इटनली का 1.3 प्रतिशत है। जिस यूरोप की दुहाई देते हुए पूरी दुनिया आगे आ रही है, वहां ग्रीस, आयरलैंड, पुर्तगाल और स्पने सबमें दो प्रतिशत है। पूरी दुनिया चाहती है कि हमें भारत में आकर निवेश करना है, तब हम चाहते हैं कि हमारा जो 2,000 करोड़ है, उसे 10,000 करोड़ किया जाए। यह एडवर्स एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बिजनेस में इस तरह से बढ़ावा देना, मुझे लगता है

हायरएंड रिस्क हो जाता है। अगर हमें पब्लिक इंटरेस्ट को देखना है, तो मंत्री जी हमारा जो एक्सपोजर है फारेन ट्रेड में, वह सदन में करेंसीवाइज और कंट्रीवाइज बताएं और वह भी यूरोजोन के साथ। उसके साथ ही हमारा जो एक्सपोजर अनफ्रेंडली कंट्रीज के साथ है, वह भी बताएं।

परसों समाचार पत्र में दो बातें आई थीं। एक बात थी कि रशिया भारत को सुखोई विमान दे रहा है और दूसरी बात थी कि वहां पर भगवत् गीता पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब हमें यह तय करने का समय आ गया है कि हमें किसके साथ दोस्ती करनी है और किसके साथ नहीं। पूरा यूरोजोन और दुनिया के करीब-करीब बड़े-बड़े देश जब आर्थिक मंदी में फंसे जा रहे हैं, तो यह ओवरसीज ट्रेडिंग इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं। एक्जिम बैंक को जो अथोराइजेशन दिया हुआ है, वह 2,000 करोड़ रुपए का था।

Under the Companies Act, 1956, and also under the Banking Laws, the issued and paid up capital of a company cannot exceed the authorised capital of a company. It is a major violation of Exim Bank. किसको पूछकर, किसकी पर्मिशन से उन्होंने जो 2000 करोड़ के सामने 5415 करोड़ सिर्फ कैपिटल बताया है तो बैंक ने 3415 किस अधिकार से ज्यादा दिया है। इसकी कोई वजह है तो वह सभापटल पर रखी जाए। बैंक के डायरेक्टर और ऑडिटर ने बैलेंसशीट कैसे साइन की, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। अब दूसरी बात यह आती है कि क्या भारत सरकार ने इस मामले में किसी को दंडित किया है? साथ में इस प्रकार का वायलेशन, कैपिटल ऑथराइजेशन 2000 करोड़ रुपये का है और बाद में जो वायलेशन हुआ है वह कब से शुरु हुआ है? उसके साथ आज बैंक का एनपीए एकाउंट क्या है? एक साल में 100 परसेंट से ज्यादा एग्जिम बैंक का एनपीए हुआ है। 490 करोड़ रुपये से 930 करोड़ रुपये हो गया है। डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री यह बताएगी कि कोई भी कंपनी होती है, उसे घाटा होता है उसके एनपीए एकाउंटस होते हैं। मान लीजिए कि किसी गरीब आदमी का एकाउंट एनपीए होता है, ग्रामीण क्षेत्र का कोई एकाउंट एनपीए होता है, वह तो देश की समाज-रचना, अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए होता है। लेकिन अगर इसमें 100 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होती है तो किसे मुनाफा हो रहा है? आज एग्जिम बैंक के जो एकाउंट होल्डर्स हैं, the largest single borrower holds 13.46 per cent of the total capital fund of the Exim Bank. The larger borrower group holds 30.46 per cent of the total capital fund of Exim Bank. ये जो पहले 10 बॉरोवर्स हैं, ग्रूप और व्यक्तिगत उनकी जांच होनी चाहिए और उनमें से किसके एकाउंट एनपीए हैं उसकी भी जांच की जानी चाहिए। ये पूरा पैसा हम जो 2000 करोड़ से लेकर 10000 करोड़ कर रहे हैं, ये उन्हीं लोगों के पास जाने वाला है जिनके नाम पर अभी तक पूरा एकाउंट चल रहा है। अभी जो स्टेटस है लोन्स और एडवांस का 31 मार्च 2011 से, loans to Bank outside India is Rs.2051 crore and loans to financial institution outside India is Rs.9400 crore. जो लोन का राइटअप हुआ है वह है 254 करोड़।

सभापति जी, मैं आपका ध्यान एक दूसरे बिंदू पर आकर्षित करना चाहता हूं। दो पूर्णकालिक डायरेक्टर्स हैं। आज के समय में एग्जिम बैंक में 16 डायरेक्टर्स हैं उनमें से 13 डायरेक्टर्स भारत सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और दूसरे 3, आरबीआई, आरडीबीआई द्वारा नियुक्त होते हैं। यह बताया जाता है कि काम बढ़ा है इसके लिए दो और नियुक्त करते हैं तो जब हमारा ट्रेड पूरा नैगेटिव जा रहा है हमारा एनपीए एकाउंट सौ प्रतिशत हो गया है, तो ऐसा कौनसा काम बढ़ा है जिसके लिए हमें और दो लोगों को लगाना है, ताकि जो भी निर्णय लिये जाते हैं उनमें और भी ज्यादा विलम्ब हो या कोई ऐसी जगह पर जहां निर्णय लेने में सीएमडी या चेयरमैन सक्षम नहीं हैं। ...(<u>व्यवधान</u>) अगर दो के विरुद्ध मतदान करने की बात है तो अलग है। सर, मैं कंक्लूजन पर आ रहा हूं।

महोदय, मौजूदा वैश्विक मंदी के मद्देनजर अचानक पांच गुना पूंजी में बढ़ावा करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि यूरोप, अमरीका और यूके जैसे बड़े राष्ट्र आर्थिक मंदी में फंसे हुए हैं। पूंजी में पांच गुना बढ़ोतरी को देखते हुए बैंक की उधार लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है, जो कि हानिकारक हो सकता है। इससे बैंक की वित्तीय सहायता करने की क्षमता बढ़ेगी और बिना जरूरी वित्तीय सहायता को भी प्रोत्साहन मिलने की सम्भावना बन जाती है। प्रस्तावित बिल से आयातकारों और निर्यातकारों को वित्तीय सहायता देने से वित्तीय खतरा होने की सम्भावना है, क्योंकि यह पैसा वापिस आने वाला नहीं है। इम्पोर्ट्स को अधिक वित्तीय सहायता बढ़ाने के कारण घरेलू उद्योग इनकम और विकास दर, जिसे जीडीपी कहते हैं, इस पर भी खतरा बढ़ सकता है। इसके साथ-साथ प्रस्तावित बिल में पूर्वकालीन निदेशकों की नियुक्ति की वजह से बैंक के सही उद्देश्यों को कार्यान्वित करने में विलम्ब होने की सम्भावना भी बढ़ जाती है और बैंक में वर्ष 1981 से 2007 तक 500 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक हुआ और आज वर्ष 2007 से 2011 में चार साल में सिर्फ पांच गुना जो वृद्धि हो रही है वह न्यायोचित नहीं है।

महोदय, मुझे लगता है कि इस बिल में काफी संशोधन की जरूरत है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

DR. K.S. RAO (ELURU): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill. I heard with patience the opinions and views expressed by the hon. Member, Shri Shukla from the Opposition benches. Let me submit that there is nothing wrong in highlighting and speaking on the negative points that may have been there in the provisions of the Bill or for reasons of his experience about the performance of the Exim Bank, but he expressed pessimism and focused more on the negative aspects of it than on the positive aspects. I will explain how.

Sir, he mentioned that there is global recession and the GDP growth rate in India is 6.9 per cent and the GDP growth rate in developing countries is 21.5 and all that and from all those countries people who wanted to come to India to take up business and invest in manufacturing sector and import, export and business, how is it that Government of India is increasing capital to promote Exim bank to encourage more and more exports? I wish to bring it to the knowledge of my colleagues here that there are not only developing countries in this world, but there are also to be developed and being developed countries. There is ample opportunity for the Indian corporate sector to invest and gain profits out of continents like Africa, Asia, the Gulf and many other continents. Today if we were to see the presence of one country in all these countries, we would find only one country and that is China. They are entering in a big way -- whether in the manufacturing sector, infrastructure, education and even agriculture – in these continents. So, there is ample need and also necessity for us to encourage our corporate sector to spread their activities in such countries, be it even in the manufacturing sector.

Sir, as a matter of example I would like to cite one instance. One of the major commodities that is being imported in this country is edible oil and pulses. Lakhs and lakhs of acres of land is being offered by African countries for those who want to take up agriculture in their country. China is taking advantage of this offer. I have brought this fact to the notice of the hon. Minister as well. If we lose this opportunity to encourage our farming sector and our farmers, the cooperative societies aided by the State Governments and the corporate sector to take up this opportunity where land is being offered almost free of any lease rent, then tomorrow they will gradually increase the lease rate for agriculture. Already in these last two to three years since the time they started offering the land for agriculture, they have now reduced the lease period of the land from 90 years to 60 years and also they have increased the lease rate from 5 dollars to 10 dollars to 20 dollars to 100 dollars per acre.

Why is it so? It is because of you. If some NPAs are there somewhere, we cannot burn them and we cannot stop the activity. China could do all this because the Government is supporting the corporate sector there and they are going in a big way. They are making tonnes of money and earning foreign exchange. Here, we have a trade deficit in our country. It is a necessity to earn foreign exchange from all these countries. Our corporate sector was not strong enough at the time of Independence and that is why, the Government has encouraged the public sector. But now the corporate sector has come to a stage where they can even extend their activities not only here but outside India also.

For example, consider the cement industry. There was shortage of cement for some time in this country. But today, there is surplus. If a cement company is started once again, it will lose in India and if the same company can do wonderful things if they start it in Africa. But who will finance them? Finance is not in terms of rupees but it is in dollars. It has to be financed in dollars. Where is the dollar for the corporate sector?

The EXIM Bank has to come into operation. It is only the EXIM Bank which can do it. In fact, I had requested the then Finance Minister, Shri Chidambaram in those days to keep 15 per cent of the foreign exchange reserves for financing the corporate sector to start industry outside the country. He did not agree with me at that time. Later, the Government has agreed to allocate 15 per cent of the foreign exchange.

So, please do not limit our corporate sector. You are very capable. Our people are very competent and intelligent. They are determined and hard-working. They have innovative ideas. Even the farmers are innovative. They can raise any crop. If the hon. Minister says that some hybrid variety has come up, the entire farming community is prepared to adopt that hybrid variety and increase production. If this is the situation, is it not the duty of the Government to encourage all these entrepreneurs to go to all those countries? Of course, it is not the USA. I can say with authority today that if you are to finance our corporate sector, they will excel even in USA, Europe and UK. We are aware that the health care sector in this country has gone up so much that the Britishers are coming to India for treatment. ...(*Interruptions*) The pharmaceutical industry in India has gone ahead so much that even America is lagging behind. ...(*Interruptions*)

So, to say that it is highly risky to increase the capital from Rs.200 crore to Rs. 400 crore to promote it and so, it should not be done is not reasonable. It is not deeply thought. They have not gone into the conditions in the globe. I can understand at a time when globalization was not brought in. Now there is globalization. If the price is down in one country, it has got an effect on our country also. In such a situation, we should not think in terms of limiting only to India or one particular State. We must see as to how there will be a reaction due to certain things that are happening outside India.

Why are we suffering? We are suffering because of the melt-down in USA. Our economy is strong enough. But still that impact will be there in our country. It is not about the increase of the equity from Rs. 2000 crore to Rs. 10,000 crore at one time.

15.59 hrs (Shri Satpal Maharaj *in the Chair*)

It is authorizing the Government to increase the capital from Rs.2000 crore to Rs. 10,000 crore as and when required. Even if the Minister was not to bring this Bill today, in fact, all of us should have asked him to bring it immediately and encourage the Export Import Bank to finance our corporate sector.

As I told earlier, why are we discussing about agriculturists every day? It is because there is no remunerative price but the consumer price is very high. All that is because there is terrible shortage of oilseeds in this country.

16.00 hrs.

That is why I made a request to the hon. Minister of Agriculture in this regard. We are importing Rs. 39,000 crore worth of edible oil every year. Indian farmers are ready to produce all that in India itself if he is given Rs. 15 of subsidy per kg. of oil. This is for the oil that is being imported from other countries. He brought the duty from 20 per cent to zero. That means he

has foregone the income also. But when our farmers are ready to produce all that oil worth eighteen lakh tonnes, the Government is not coming forward. It is a pathetic condition. Shri Sharad Pawar ji, please take care of it. You are not doing any big thing to the farmer. In fact, they are doing a great service to the nation. If they produce that kind of oil, then they are saving Rs. 39,000 crore of foreign exchange. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please summarise.

...(*Interruptions*)

SHRI K.S. RAO (ELURU): I once again request the hon. Members from the Opposition to please find fault if there is anything wrong in the Bill, which I do not oppose. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Let him speak. Shri Rao, please summarise now.

SHRI K.S. RAO : Just because I am fielded from the Government side, I am not supporting out-right. There are certain things which the Government also has to do. I am finding fault with the Government for not giving remunerative price to the oil seed farmers and then importing oil regularly, every year. What is this pathetic condition! My humble request to the hon. Minister who is sitting here is to think of supporting the Exim Bank. Shri Namo Narain Meena is doing a wonderful job. Instruct the Exim Bank to increase its business multifold. Let them encourage the corporate sector in this country to go to the African countries. Let them take up all the activities, right from manufacturing, infrastructure to agriculture. It is only in the interest of the nation.

MR. CHAIRMAN: Shri Rao, you made your point. Please conclude.

SHRI K.S. RAO : NPAs are there, and NPAs will be there. There will be some genuine failures and there will be some motivated failures with false intentions. You find fault with such cases where there are false intentions of cheating the banks. In those cases you can say that the Government should take action. There is nothing wrong in it. But in certain cases there are genuine failures. For that reason we cannot close down the banks. We cannot discourage the banks. In spite of making provision for the NPAs, the Exim Bank is earning profit every year. So, in such circumstances, I would humbly request the entire House to support this Bill unanimously and encourage the Exim Bank to go in a big way, not one-fold or two-fold or ten-fold, it should be hundred-fold increase in foreign business, including agriculture.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे भारतीय निर्यात-आयात बैंक संशोधन विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस विधेयक में 1981 का संशोधन है और 1981 में हमने पांच अरब रुपये से इसकी शुरूआत की थी और निर्यात-आयात बैंक की प्राधिकृत पूंजी को बिल में 20 अरब रुपये से बढ़ाकर एक खरब रुपये किया गया है। यह भी कहा गया है कि समय-समय पर यदि आवश्यकता समझेंगे तो इसकी धनराशि को हम और भी बढ़ा सकेंगे। निर्यातकर्ताओं और आयातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि यदि उन्हें धन की कोई कमी होगी को समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार हम धनराशि बढ़ाकर आयात-निर्यात को बढ़ावा देंगे।

लेकिन जहां तक देखा गया है कि वैश्विक मंदी के बढ़ने से डॉलर के मुकाबले रूपये में जो कमजोरी आई है, उससे निर्यातकों को कुछ राहत मिली है। लेकिन जो कठिनाइयां उनके सामने हैं वे आज भी बरकरार हैं। अगर हम भारत और चीन की तुलना करें तो चीन में भी भारतीय निर्यात की नई संभावनाओं को हमें खोजना पड़ेगा। हमने देखा कि आज चाइना से बने तमाम सामान यहां पर सस्ती दरों पर आते हैं लेकिन उस प्रतिस्पर्धा में देखें तो भारत कहीं भी खड़ा नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए हमें उनके मुकाबले में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत करेंगे तो हमें कृषि की अर्थव्यवस्था की ओर ज्यादा प्रोत्साहन देना पड़ेगा। अगर हम आयात-निर्यात को प्रोत्साहित कर रहे हैं, नए निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं तो वहीं पर हमें कृषि अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन देना पड़ेगा। देश में आर्थिक संकट के बीच आईटी क्षेत्र एवं तमाम क्षेत्रों में नौकरियों में कमी आई है। बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी से लड़ने के लिए हमें समुचित व्यवस्था करनी पड़ेगी। भर्ती के मामलों के आंकड़ों को देखा जाए तो टेलिकॉम और आटो क्षेत्र में भर्तियां घटी हैं। दूसरी तरफ जो हमारे चमड़ा निर्यातक हैं, उनको बढ़ाने के लिए हमें कच्चे माल के आयात पर शुल्क और उससे जुड़े करों को घटाना होगा तभी हम प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। रबड़ के आयात पर शुल्क कम करने की दिशा में हम एक पहल करेंगे तभी जा कर आयात-निर्यात को बढ़ावा दे सकेंगे। अगर तुलना कर के देखें तो चाइना आगे बढ़ कर सन् 2020 तक खाड़ी देशों का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार बनने का दावा कर रहा है। उस ओर हम अभी बहुत पीछे हैं। हमने अभी केवल वर्तमान समय में सन् 2011 की बात की है जबकि चाइना सन् 2020 की बात कर रहा है। हमें तुलनात्मक रूप से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी और और हमें एक कोशिश और भी करनी पड़ेगी कि देश की नई पीढ़ी को प्रतिभा कौशल और उन्नयन से सुसज्जित करके उनको निर्यात की डगर पर आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना पड़ेगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आज बैंको के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सरकार के प्रस्ताव आए हैं कि बैंको में जनरल मैनेजर के जो पद हैं उनको कम करने की बात की गई है। हम अगर आयात निर्यात में इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं तो बैंकों में भी प्रतिस्पर्धा होगी। हमें कोशिश करनी होगी कि विदेशी बैंकों के साथ हमारे बैंक प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसके लिए हमें अपने कर्मचारियों प्रोत्साहन और बढ़ावा देना होगा। जनरल मैनेजर के जो पद कम करने की बात हो रही है उस पर भी गंभीरता से विचार करें। बैंकों में समुचित तरीके से कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या बढ़नी चाहिए, तभी हम विदेशी बैंकों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): महोदय, यह जो एक्पोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ इण्डिया एक्जिम विधेयक आया है, इसमें पहले पांच सौ करोड़ फिर एक हजार करोड़ और आज दस हजार करोड़ तक का पूंजी निवेश आया है। मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। लेकिन जहां तक हिंदुस्तान में बैंकिंग सिस्टम का हम लोगों का अनुभव है, उसको देखते हुए एक्सपोट गिर रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है। इन बैंकों की एफिशिएंसी के बारे में क्या मॉनिट्रिंग हैं, इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर सिर्फ पूंजी बढ़ाने से ही काम बन जाएगा तो हमारे ख्याल से यह ठीक नहीं हैं। क्योंकि इसमें जनता का पैसा लगा हुआ है। मैं पहली अपत्ति यह कहना चाहता हूँ कि इसकी मानीट्रिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। चूंकि इसमें हाई रिस्क में हाई मनी खर्च हो रहा है, इसकी मानीट्रिंग के लिए एक ऑपेरेटिव सिस्टम होना चाहिए।

दूसरा, हमारा सुझाव यह है कि मैं अभी कमेटी में विदेश गया तो अब हम लोगों को अमेरिका और यूरोप से हटकर, अब मार्केट एकदम से सैचुरेशन प्वाइंट पर है, अब लुक ईस्ट देखना चाहिए, अफ्रीका देखना चाहिए और अन्य ऐसे देश हैं, जहां पर कोई ज्यादा व्यापार नहीं है। उन पर भी हम लोगों को बात करनी चाहिए। मैं आपसे यह बताना चाहता हूं, अभी मैंने बिजनेस इंडिया में पढ़ा, मार्च 2010 से 2011 तक 43.92 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है। इसमें बढ़ोत्तरी तो हुई है, लेकिन इम्पोर्ट में 23 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई है। ट्रेंड जो है, इम्पोर्ट बढ़ रहा है और उस रेश्यो से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, जो भी इसका एक्सपर्ट सिस्टम हो, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई इकोनॉमिक विजर्ड नहीं हैं, जिससे एक्सपोर्ट बढ़े, वह करना चाहिए।...(व्यवधान) धन्यवाद, ये तो पत्रकार हैं, अखबार के मालिक हैं, ये कहते हैं अखबार सब कर सकता है, ऐसा हो सकता है, जीसस क्राइस्ट ने कहा, "He saw there was a light. He saw there was a night." ये तो अखबार वाले हैं, ये तो कह ही सकते हैं, लेकिन मैं अपनी अक्षमता स्वीकार करते हुए यह कहता हूं।

दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ऑपरेशनल कॉस्ट, जैसे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनलाइज बैंक हैं, उनकी मानसिकता बिल्कुल खराब है। गांव में वे जिस तरह से परेशान करते हैं, अगर यही सिनेरियो एक्जिम बैंक का वहां है तो यह फॉरेन बैंक से कम्पीट नहीं कर पायेगा। मैं चाहता हूं कि इनके ऑपरेशनल ऑस्पेक्ट में भी कोई न कोई बात को सुचारू रूप से देखा जाये। दूसरा, हम यह कहना चाहते थे कि इन बैंकों में पब्लिक मनी और पब्लिक ट्रस्ट इन्वॉल्व्ड है। The greater is the risk, the greater is the care and caution. अंत में मैं यह कहना चाहता था कि अभी मैं पिछले ब्रेक में दक्षिण अफ्रीका गया था। अभी भी वहां रेल, पॉवर, रोड आदि इफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी जरूरत है। इस बैंक में भी प्रोविजन है, जैसा कि राव साहब कह रहे थे कि इन्हें 85 परसेंट तक लोन मिल सकता है तो यह न्यू मॉर्केट क्यों नहीं हम एक्सफ्लोर करते? अगर न्यू मॉर्केट एक्सफ्लोर करें, जैसे चाइना कर रहा है, तो एक्जिम बैंक में जो पब्लिक ट्रस्ट इन्वॉल्व्ड है, वह पूरा हो सकता है। मैंने अभी माननीय कॉमर्स मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट पढ़ा। हिन्दुस्तान में हमने एक नया फैशन पार्लियामेंट में देखा कि यहां टारगेट बड़ी जल्दी फिक्स कर लेते हैं। जब मैं शुरू में आया तो सरफेस ट्रंसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम 20 किलोमीटर सड़क रोज बनायेंगे। जब हम लोगों ने क्रॉस एग्जामिन किया तो वह 6 किलोमीटर निकली। माननीय शर्मा जी का एक स्टेटमेंट अखबार में आया था कि वर्ष 2011 में उनका टारगेट 300 बिलियन एक्सपोर्ट का है। अभी आज के दिन इम्पोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। या तो फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने सीरियल स्टॉर्ट कर दिया जाये, हम वही सीरियल देखें। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, यह बहुत अच्छी पूंजी बढ़ायी गयी है, पूंजी और भी बढ़ायी जाये, लेकिन इस पूंजी के साथ उसका केयर एंड कॉर्सन, उसकी मानीटरिंग, उसकी देखरेख और नये फाइनेंशियल ग्राउंड्स, नये-नये रास्तों में जहां पर और हमारे कम्पटीटर हैं, अगर हम वहां जायें तो मुझे सफलता काफी नजदीक लग रही है।

श्रीमती मीना सिंह (आरा): महोदय, मैं भारतीय निर्यात-आयात बैंक (संशोधन) विधेयक, 2011 पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। जहां तक मैं समझ पायी हूं कि इस संशोधन के साथ निर्यात-आयात बैंक की प्राधिकृत पूंजी को 20 अरब रूपये से बढ़ाकर एक खरब रूपये तथा भविष्य में सरकार प्राधिकृत पूंजी को आवश्यकता के अनुसार बढ़ा सकती है। साथ ही सरकार निर्यात-आयात बैंक में दो पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति कर सकती है।

महोदय, मोटे तौर से इस संशोधन से निर्यात-आयात बैंक को तथा देश के निर्यातकों तथा आयातकों को लाभ मिलेगा, परंतु मैं समझती हूँ कि सिर्फ कानून बना देने से या उस कानून को लागू कर देने से चंद लोगों को फायदा हो तो उससे देश को फायदा नहीं पहुँच पाता है। हमारे देश का आयात-निर्यात व्यापार मुख्यतः अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ है, परंतु वैश्विक मंदी के इस दौर में अमेरिका और यूरोपीय देशों में खर्चों में कटौती की जो प्रक्रिया चल रही है, उससे भारतीय निर्यातकों को ढेर सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर हमारे देश का चमड़ा निर्यात जो लघु और मझौले उद्योग में आता है, उनमें लागत बढ़ने के कारण उनके मुनाफे में करीब 50 प्रतिशत की कमी आई है। फिलहाल विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा महज एक फीसदी है जबकि चीन का हिस्सा 10 फीसदी है। हमें विश्व के निर्यात बाज़ार में चीन से चुनौती मिल रही है। उसका सामना करने के लिए हमारे निर्यातकों को वर्तमान से दो फीसदी कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए ताकि प्रतिस्पर्द्धा के इस दौर में हम दूसरे देश के निर्यातकों का सामना कर सकें।

महोदय, मैं यहाँ यह भी बताना चाहूँगी कि हमारे देश के निर्यात ऋण चीन सहित दुनिया के अन्य देशों की तुलना में ज्यादा हैं, इसलिए देश के आयात-निर्यात व्यापार को सुस्ती से निर्यात के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। इसी के साथ मैं अंत में एक बात और कहना चाहूँगी कि इस संशोधन विधेयक के पास होने के बाद सरकार यह प्रयास ज़रूर करे कि इसका लाभ छोटे और मझौले व्यापारियों को भी मिले। ऐसा न हो कि इसका लाभ सिर्फ मुट्ठी भर बड़े व्यापारियों को मिले। इसी सुझाव के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करती हूँ।

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Sir, this Bill is to increase the authorized capital of Exim Bank from Rs.2,000 crore to Rs.10,000 crore. With the increased authorized capital, this Exim Bank must extend more support to traditional sectors like khadi, handloom, fisheries, cashew, etc., which are more labour intensive. Presently, the Exim Bank is not giving the kind of support expected to be given to these sectors.

One of the major objectives of setting up the Exim Bank in 1982 was to promote our international trade. In this regard, I would like to make three brief points. First is regarding the system of data collection. Recently, the Commerce Ministry has scaled down its estimate of exports. According to the Commerce Ministry's figure, exports grew up by 33.2 per cent to reach 197.2 billion dollars in April-November, 2011-2012. However, after the revision, the actual value was lowered by nine billion dollars than the official estimate. Still worse, there is difference between seven billion dollars between the figures of RBI and the Commerce Department. This raises a question mark over the efficiency and credibility of the system of our data collection. So, a more scientific system of data collection must be put in place. Either, there should be a single agency or more coordination between multiple agencies of data collection is needed.

Sir, the second point is regarding the trade deficit. The growth of our export has plummeted to a mere 4.2 per cent in recent months. At the same time, the imports are up by a whopping 29.1 per cent. So, this has led to a widening of our trade deficit. In the entire fiscal year, the trade deficit may be between 150 billion dollars and 160 billion dollars. With China alone, we are going to have an increase in the trade deficit by three fold from 23 billion dollars to 63 billion dollars. This exposes the weaknesses in our strategy. It means that the strategy of opening up of our trade has not benefited us, but, in fact, it has benefited other countries. In this context, we need to have a thorough introspection on our Free Trade Agreements especially with the European Union and ASEAN countries.

My last point is regarding the depreciation of rupee. The value of rupee was 45 per dollar a year back and it has fallen sharply to Rs. 53 recently. The Government is taking a position of non-intervention in this matter. All other countries, whose currencies have depreciated, are intervening to stabilise their own currencies. Even China has intervened to stabilise their currency. So, the idea of non-intervention is a bogus idea.

The depreciation of rupee is taking place because the FIIs are pulling out huge amounts of money. Again this exposes the weakness in our strategy because we have built our foreign exchange reserve not on the basis of our export growth but we are heavily dependent on short-term capital infusion. In this context, we must keep in mind the experience of East Asian countries in the late 1990s. Hence, it is high time for the Reserve Bank of India to consider capital controls in order to prevent such sharp falls in rupee value.

Sir, I would like to conclude with the expectation that the Export-Import Bank of India will extend more support to traditional sectors which are more labour intensive.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I rise to participate in the discussion on the Export-Import Bank of India (Amendment) Bill, 2011.

Sir, this is a very small, innocuous bill and there is nothing much to say, but it has large impact on our export and import facilities that have been provided. As has been said, this Bank was initially created in 1981 as a corporation to provide financial assistance to exporters and importers and for functioning as the principal financial institution for coordinating the working of institutions engaged in financing the export and import services with a view to promote the country's international trade. This is the basis on which this Bank was established. This Act has been amended six times namely in 1985, 1988, 1998, 1999, 2005 and 2006. Again this amendment has come in 2011.

I feel it is the responsibility of this Parliament to go into the functioning of this Bank. There are five or six issues which should be discussed. As this Bank is specially established to promote international trade, we should also find out as to how it has helped our indigenous traders, industrialists, how it has helped in opening of branches outside the country and how it has brought in support mechanism for our exporters and importers.

Sir, the basic idea of this Bill today has two aspects. One is to increase the authorized capital from Rs. 2,000 crore to Rs. 10,000 crore and the other aspect is to appoint two full time Directors by the Central Government. These are the two amendments which are before us for consideration. I would like to know from the hon. Minister as to how the Micro, Small and Medium Enterprises are benefited by this Bank.

I would like to know whether they have gone into this very aspect before coming with this amendment. If it is so, then we should be made aware about it because major thrust should be on the medium and small scale enterprises where more thrust should be given as has been said these are labour intensive and more people are engaged in these industries. It should not be that the funds, which are being created by this Bank, which are supported by this Bank, are cornered by the big industries who are engaged in exports or imports.

I would also like to know whether in export and import food items are being encouraged; not only the food stock, like grains

or *dal* or whatever it is, but there are food items which need to be encouraged to be exported and at limited level we are also importing those food items. I would like to know whether this Bank is catering to that need.

We have Most Favoured Nations Agreement with many countries and that MFN Status we have with Central Asian countries, with Latin American countries, with ASEAN countries and with African countries. Other than that we have a special arrangement with the SAARC countries where the trade facility has gone up within the last five to seven years to a great extent. But there the difficulty is still there. Suppose an industry which is sending its goods keeping the United States market in view, but it sends it to Mexico or to certain Latin American countries and there it can cope up with the competition which China, while dumping all those products in the United States, capturing that market. We have MFN Status with Mexico or with Brazil which will send those products there and from there it goes to the American market. But is EXIM Bank helping these Indian exporters in a big way that needs to be looked into?

The other aspect which I would say is that we have a greater presence in the European Union market. We also look into the Central Asian countries where we are going in a big way to import oil from Central Asian countries other than the Gulf countries. So, Latin American countries, European Union countries, the ASEAN countries and the African Continent, either it be the Eastern Coast or in the Western Coast of African Continent, the EXIM Bank should make its presence felt.

Another aspect which I would like to say here is that in this Bill there is an Annexure which has been added and there I would expect the hon. Minister to come out with certain statement because that is a cause of concern of many. Here it is mentioned that if the Chairman or Managing Director is going to relinquish his job before time then he has to give three months' notice. That is a provision which needs to be there, 'but such salary and allowances as may be determined by the Central Government'.

As this is a Government sponsored Bank, this provision, no doubt, is required to be there. But the greater question which actually bothers many of us in this country is, should the Government determine the salary of the Chairman and Managing Director of financial institutions? I am not making a distinction between private banks or Government authorised banks. Should the Government determine the salary of the Chairman and Managing Director or should we leave it to the market forces which can determine how much salary is to be given?

Today, there is discontentment among Chairmen and Managing Directors of the public sector banks and the Chairmen and Managing Directors of private banks. The salary component is topsy-turvy, though private banks give more salary where as our public sector banks are giving less salary. That is not being determined by the Government. I think the Government should look into this aspect and take a decision. Are we going to curtail that or do we have to bring a semblance between them? That needs to be determined.

With these words I conclude.

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to take part in the discussion on Export-Import Bank of India (Amendment) Bill, 2011. The Bill under discussion seeks to increase the authorised capital of the EXIM Bank from two thousand crores of rupees to ten thousand crores of rupees with the provision that the Centre may further increase the said capital up to an amount that it may deem necessary. It is not one-fold or two-fold increase; it is five-fold increase in the authorized capital. The purpose of the increase, the aim of the increase is to enable the Bank to take the higher export credit exposure and enable it to borrow funds to disburse under export Line of Credits.

Now, before us, the question is whether the EXIM Bank is functioning as per our expectation. But the answer is that definitely it is not functioning as per our expectation. My submission is that the EXIM Bank should not encourage the big corporates, as was just now pointed out, like Tata, Birla, Ambanis. The EXIM Bank must encourage small and medium industries. Then only a large number of our export industries and markets will grow up and they will survive. So the EXIM Bank should come forward to finance our people, to promote our export industry, to start the business and establish abroad our industries. Japan is following the same practice; Russia is following the same practice; South Korea is following the same practice; China is following the same practice. Why not India? So, my submission to the hon. Minister is that the aim of the Bank should be to promote our people, to promote our export industry in other countries. For that, we have to promote Special Economic Zones; we have to encourage our people; we have to encourage production. For that purpose, we must be very liberal in providing loans, financial assistance and some facilities also. In that line, the Minister has to think.

While supporting the Bill, I differ from our hon. Minister in one thing. I understand the need to raise the capital of the Bank to the extent of ten thousand crores of rupees but I am not able to support the provision seeking further increase in the authorized capital without getting the approval of the Parliament. On each and every opportunity, the Centre tries to bypass the Parliament in a routine manner. This is deplorable. The supreme institution, I mean our Parliament, has become the least respected organ of the Government in the eyes of the UPA Government. So, I think and I feel that there is no need to incorporate the clause for further increase without getting the approval of the Parliament.

What is the justification in appointing two whole-time Directors by the Central Government? What is the justification that the UPA holds? In the Statement of Objects and Reasons, the Minister does not provide any reason or answer for that. The hon. Finance Minister also, while introducing the Bill, did not spell out any justification. So, the hon. Minister has to explain and clarify it. Unless it is absolutely necessary, there is no need for two whole-time Directors. The existing arrangement may continue. This is what I feel. With these remarks, I conclude.

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Sir, I thank you for giving me this opportunity.

In this Bill, the Government has brought two issues. First, the Government is increasing the authorization capital from Rs. 2,000 crore to Rs. 10,000 crore. Second, the Government is appointing the whole-time Directors.

When the whole-time Directors are appointed, the Government should fix the targets and responsibilities on them properly. Their selection process is also very important. It should be kept in the mind at the time of appointment of whole-time Directors. के. एस. राव साहब सदन से चले गए। उन्होंने अपनी बात कहते हुए दो ईश्यूज रेज किए। I am completely opposing what Shri K.S. Rao has said. वह एक बात कहते हैं कि अफ्रीका में जाकर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करो। इंडिया में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा है, अफ्रीका में जाकर पैसा लेकर उधर का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करेंगे, this is not the correct way. दूसरा, इफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अफ्रीकन कंट्रीज में काफी स्कोप है। इंडियन इफ्रास्ट्रक्चर में इसकी काफी रिक्वायरमेंट है। This type of fund should not be mis-utilised for such type of works.

सभापति महोदय : संक्षिप्त करिए।

श्री नामा नागेश्वर राव : यूपीए के कांग्रेस मेंबर जो बोल रहे हैं, इस तरह से मिस-यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। फुल फोकस एक्सपोर्ट के ऊपर होना चाहिए। फुल फोकस एक्सपोर्ट्स के ऊपर रहने के लिए इंडिया में कई एसईजेड्स लाए गए हैं। इन एसईजेड्स में भी हैंड्रेड परसेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, so that we can get more revenue. फॉरेन रेवेन्यू को लाने के बहुत चांसेज हैं। आज के दिन फॉरेन रेवेन्यू का ट्रेड डेफीसिट ही बहुत ज्यादा है। रूपए का डेप्रीसिएशन मेजर ईश्यू है। इसे कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, इस ओर ध्यान देना चाहिए।

इंडिया में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। इंडिया में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को अगर एग्जिम बैंक सपोर्ट करेगा, तो वर्ल्ड मार्केट में हम लोग कंपीट कर सकते हैं। आज के दिन यह नहीं हो पा रहा है। इंडियन इंडस्ट्री का इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट करने के लिए मेजर ईश्यू इंट्रेस्ट बर्डेन है। एग्जिम बैंक से मैक्सिमम सपोर्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंड हैंड्रेड परसेंट रेवेन्यू, who is getting the revenue from foreign currency, इसके लिए होना चाहिए। सबसे ज्यादा स्माल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान देना चाहिए। स्माल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करिए, आपने अपनी बात कह दी है।

श्री नामा नागेश्वर राव : महोदय, दो मिनट का समय दीजिए। ये लोग जितना इनक्रीज करेंगे, लेकिन दस हजार करोड़ रूपए मेजर कारपोरेट कंपनीज को नहीं जाना चाहिए। अगर दस हजार करोड़ रूपए चार-पांच कंपनीज को देंगे, यह सब देना गलत होगा। एग्जिम बैंक ने अब तक जो दिया है, वह मैक्सिमम परसेंटेज मेजर कारपोरेट सेक्टर्स को दे रहा है। इसका मैक्सिमम फंड यूटीलाइजेशन स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को देना चाहिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड को देना चाहिए, एक्सपोर्ट फूड इंडस्ट्रीज पर ध्यान देना चाहिए। इन सब चीजों को आप इसमें इंक्ल्यूड करेंगे, तो हम इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, सरकार यह बिल लायी है। सन् 1981 में आयात-निर्यात बैंक की स्थापना के लिए विधेयक पास हुआ था। वर्ष 1982 में इनकी पूंजी की क्षमता 500 करोड़ रूपये थी। वर्ष 2007 में इन्होंने पूंजी की क्षमता 500 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 2000 करोड़ रूपये कर दी। अब यह कहते हैं कि इसे बढ़ा कर 10 हजार करोड़ रूपये करेंगे। ये एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट में कितना उदार हैं? बड़े पूंजिपतियों के द्वारा जो कारोबार होता है उसके लिए ये कितना उदार हैं? इन्होंने तुंत पांच सौ करोड रूपये से दो हजार करोड़ रूपये, दो हजार करोड़ रूपये से दस हजार करोड़ रूपये और फिर अधिसूचना कर उसको बीस हजार करोड़ रूपये या तीस हजार करोड़ रूपये कर देंगे। ये बहुत उदार हैं।

हिन्दुस्तार की क्या स्थिति है? हम दुनिया के आबादी के 17 फीसदी हैं। दुनिया का छठा हिस्सा हिन्दुस्तान है। यहां पूरे विश्व की 2.4 फीसदी जमीन है लेकिन व्यापार और कारोबार में हिन्दुस्तान का हिस्सा एक फीसदी है। व्यापार में चीन का पूरे विश्व में 10 फीसदी हिस्सा है। हम कहां पर हैं? फिर भी यह कहते हैं कि हम आयात-निर्यात से विश्व के व्यापार में वृद्धि करा देंगे और सहायता करेंगे। हम कहां पर खड़े हैं, कहां पर कमी है और कहां पर गड़बड़ी है? इन सब का मैं अभी उद्घाटन करता हूं।

विश्व व्यापार में इन्होंने वृद्धि का जो दावा किया है अब उसे देखा जाए। आयात बढ़ रहा है और निर्यात घट रहा है। आयात-निर्यात में असंतुलन बना हुआ है। दुनिया में

हमारा व्यापार एक फीसदी है और उसमें भी हमारा आयात बढ़ रहा है और निर्यात घट रहा है। आज अमेरिका और यूरोप मंदी के शिकार हो रहे हैं। वर्ष 2008 के बाद फिर मंदी हो गई। अपने देश पर भी मंदी का खतरा है। रूपये का भाव घट रहा है। एक डालर का मूल्य 45 रूपये से 56 रूपये हो गया। इससे निर्यातक को कुछ फायदा हो रहा है लेकिन आयातक के प्राण छूट रहे हैं। सरकार ने इसके लिए क्या उपाय किए या क्या कर रहे हैं, बताएं। रूपये का अवमूल्यन हो रहा है और मंदी के दौर से हम गुजर रहे हैं। वह खतरा होने वाला है। आयात बढ़ रहा है और निर्यात घट रहा है। रूपये का दाम घट रहा है। उस के लिए इन्होंने क्या उपाय किया है? केवल पूंजी को बढ़ा दिया जाए। यह विधेयक बस दो बातों के लिए है। पूंजी दो हजार करोड़ रूपये से बढ़ा कर दस हजार करोड़ रूपये कर दी जाए और उसमें पूर्णकालिक दो नए डायरेक्टर बहाल करेंगे। यह पहले नहीं था। बस यही दो बातों के लिए ये विधेयक लाए हैं।

इन्होंने दावा किया है कि हम विश्व व्यापार का कारोबार एवं आयात निर्यात को बढ़ाएंगे लेकिन ये अभी तक कहां पर हैं? सरकारी बैंक का बोलबाला है। जब पूंजी घटती है उसी समय सरकार का खजाना खुल जाता है। लेकिन प्राइवेट बैंक का काम अच्छा चल रहा है और सरकारी बैंक का काम प्राइवेट बैंक की तुलना में कमजोर चल रहा है। इसलिए हम को एक स्पेसिफिक सवाल इन से पूछना है कि मूडी ने अभी एक रिपोर्ट दी है। इसने अपने बैंक के कारोबार का रेटिंग घटा दिया है। उसके सुधार के लिए आपने क्या उपाए किए हैं। केवल बड़े आदमी और कारपोरेट अपने सामान विदेश में भेजेंगे और मंगाएंगे उनकी सहायता करेंगे। लघु और मझोले उद्योगों के लिए आप के पास क्या योजना है? उनकी सहायता कैसे होगी ताकि उनका भी सामान विदेश में जाए और आए। हमारे किसान को तो कोई पूछने वाला नहीं है? किसान भी बहुत सामान का उत्पादन करते हैं। अभी नेता जी कह रहे थे कि हम चीनी निर्यात करने की स्थिति में हैं लेकिन वह आयात हो जाती है। इसका क्या कारण है? इसमें क्या पेंच है? इनकी तरकीब क्या है? ये सब बातें साफ होनी चाहिए। इसलिए शोध और विकास में इनकी क्या योजना है? आयात-निर्यात के कारोबार में रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट विंग कुछ है। एक्जिम बैंक ने क्या किया है? उनकी क्या योजना है? हम यह जानना चाहते हैं। आप व्यापार में घट रहे हैं। आप आयात बढ़ा रहे हैं और निर्यात घटा रहे हैं। इस स्कीम के लिए रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट विंग की कोई योजना है?ऊर्जा की कमी है। हिन्दुस्तान विद्युत संकट से गुजर रहा है। रिन्युवल एनर्जी, सूर्य वाली एनर्जी के बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। क्या रिन्युवल एनर्जी के लिए इनकी कोई योजना है, मैं यह जानना चाहता हूं? मै एग्ज़िम बैंक के बारे में पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ उनकी पूंजी बढ़ी दी जाए, खर्चा बढ़ा दिया जाए और काम घटा दिया जाए। ऐसे नहीं चलेगा। हम काम भी देखेंगे।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : विदेशी मुद्रा संसाधन बढ़ाने की इनकी क्या योजना है, हम जानना चाहते हैं। देश जानना चाहता है कि जो विदेशी संसाधन हैं, उसे बढ़ाने की इनकी क्या योजना है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मान्यवर, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : जापानी, स्विस, ताइवान, इन सभी बाजारों में हमारी जाने की क्या योजना है।...(व्यवधान) ग्रासरूट से जो काम हो रहा है, ग्रासरूट पर इनकी क्या पहल है। हम जानना चाहते हैं कि जो लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग, हमारे किसान थोड़ी-थोड़ी पूंजी लगाकर बढ़िया सामान उत्पादित करते हैं, जो एक्सपोर्ट करने लायक हैं, उनके लिए इनकी क्या योजना है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है, आपने अपनी भावना व्यक्त कर दी है।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : बड़े-बड़े लोग चल रहे हैं लेकिन गरीब, कमजोर व्यक्ति को कहा जाता है कि आपके लिए जगह नहीं है, जाइए। ऐसे नहीं चलने वाला है।...(व्यवधान) इसलिए ये इन सब सवालों का जवाब दें तब एग्ज़िम बैंक और इनकी पूंजी बढ़ाई जाएगी। ...(व्यवधान) इन सब बातों का साफ जवाब आना चाहिए, तब यह पास होगा।

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Respected Chairman Sir, we know that the EXIM Bank is a hundred percent Government concern. Therefore, the proposal to increase the authorized capital from 2,000 crores to 10,000 crores of rupees is a welcome proposal and there is no reason to oppose it. I also support this Export Import Bank of India (Amendment) Bill, 2011.

But certain questions arise if the background of presenting the Bill is analysed. Since 2008 we have been hearing about the economic recession. So if that is the scenario then what is the reason for such a huge enhancement in the capital of the Exim Bank which primarily deals with the export and import of the country. I request Hon. Minister to inform the House about this move.

It is well known that in India, import has exceeded export and our Balance of Payment is facing a grave crisis. Under such circumstances, who will benefit if the authorized capital is increased five times – it is not clear whether the exporters will gain or the importers will gain more.

Thirdly sir, the customers of Exim Bank of India, those who are running their businesses with the help of this bank are both exporters and importers but we should be aware of the exact ratio of the exporters-importers.

Lastly, the Exim Bank of India was established in 1989 and in the last 30 years the Exim Bank law has been amended six times. The authorized capital earlier was 500 crores which had been increased to Rs.2000 crores. Now again the amount is to increase to Rs.10,000 crores.

So all these issues must be first clarified by the Government and then the Bill should be passed. With these words, I support the Bill and conclude my speech here.

---

* English translation of the Speech originally delivered in Bengali.

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for allowing me to participate in the discussion on this Bill. I support this Bill. I would make only two points and conclude my speech.

My first point is that in the states objects, I think, bypassing the Parliament is an issue; and I would request the hon. Minister to really give us the justification as to why Parliament needs to be bypassed in framing of the capital requirements of Exim Bank. The capital requirements, in the past, also have been subjected to increases. The Act was amended in several years. It also shows that we are not applying our mind as to how much capital requirements are needed in view of the increase in business in this respect.

My second and last point is that the Exim Bank may like to look at the Look-East policy in greater details because it a policy of the Government of India. There is a need for EXIM bank to be much more aggressive in countries like Myanmar, for instance, and also in the ASEAN and SAARC regions. This will help the North-Eastern States of India to be much more aggressive in getting business in these countries. This, combined with the inland ports, which will now be made, will act as a facilitator for businesses in the future. So, there is a need to look at this. I would like the Minister to respond to this in greater detail.

With this, I thank you very much allowing me to speak.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Sir, in all 12 Members have participated in the discussion. I thank all of them for their valuable suggestions and observations and for supporting the Bill.

Before responding to the specific issues raised by the hon. Members, I would like to share the performance of the bank and the background which led to the introduction of this Bill as this will also address some of the issues raised by the hon. Members during the discussion.

The Export Import Bank of India was set up as a corporation in 1982 under the Export Import Bank of India Act, 1981 with authorized capital of Rs.500 crore. The Act was amended in the year 1999 to increase the authorized capital to Rs.1,000 crore with a provision that the Central Government may, by notification, increase the authorized capital up to Rs.2,000 crore. Through a Notification in May, 2007, the authorized capital has been increased to Rs.2,000 crore. The paid-up capital of the EXIM Bank as on date is equal to its authorized capital of Rs.2,000 crore.

The EXIM Bank's headroom for raising borrowings for financing its business growth is constrained by the Reserve Bank of India's prescribed ceiling of "10 times the Net-Owned Funds". As on March 31, 2011, the NOF of EXIM Bank was Rs.5,030 crore and the Bank's aggregate outstanding borrowings were Rs.45,128 crore leaving further headroom for incremental borrowings of about Rs.5,000 crore only.

Increased capital base will enable the Bank to sustain its growth momentum and to also meet its obligations under export Line of Credits (LOCs) on behalf of Government of India. As on March 31, 2011, the EXIM Bank had 118 operative LOCs to 53 countries, amounting to US dollar 6.3 billion. Further, on his recent visit to Ethiopia, the Prime Minister has pledged LOCs of US dollar five billion to Africa over the next three years.

The Bank's total business has increased from Rs.386 crore in 1982, its first year, to Rs.1,10,130 crore in November 30, 2011. This is the increase in business. This strong business growth has been achieved by bank with a lean professional

staff, base of just 277 officers, representing business per employee Rs.398 crore and profit per employee is Rs.2.82 crore. Its asset quality is considered good and the net NPAs at only 0.20 per cent of its loan portfolio. The net NPO is one of the lowest in the banking industry in the country. EXIM Bank has been consistently making profits since its inception and has paid dividend to the Government every year, cumulating to Rs.1228 crore so far. The bank's performance compares favourably with its peer EXIM banks in other countries as well as with the financial sector in India. Going forward the bank will continue to play a key role in export Lines of Credit, overseas investment of Indian companies and project exports from India.

Sir, now I would like to respond to some of the issues raised by hon. Members. The initiator of the discussions, Shri Shuklaji, raised that against an authorised capital of Rs.2000 crore, how is the paid-up capital of Rs.5230 crore? I would like your kind attention that there is no violation as the paid-up capital is Rs.2000 crore only. However, the figure of Rs.5238 crore mentioned by hon. Member is the net worth which includes paid-up capital of Rs.2000 crore and reserves and surpluses accumulated due to profits made by the bank. So, there is no violation.

Shuklaji raised a question about the NPA that there are lots of NPAs in the bank. That is not correct. The gross NPAs as on 31st March, 2011 were Rs.478 crore, that is, the business of over one lakh crore. As I have mentioned, the net NPA on 31st March, 2011 is only 0.20 per cent, which is among the lowest in the banking industry in the country.

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला (वडोदरा): इसका एमाउण्ट क्या है?

SHRI NAMO NARAIN MEENA: I have told the amount. It is Rs.478 crore.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): आपने एमएसएमई को कम दिया है।

16.57 hrs (Shri Basu Deb Acharia *in the Chair*)

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Shri Balkrishna Shukla also raised a question that there are so many Directors. There are 16 Directors in the Board. Why are we adding two more? Sir, currently, only one whole-time Director is on Board. Others are nominee Directors, who only attend the Board meetings. This amendment seeks to make a provision of two whole-time Directors to strengthen the management. They will be amongst the 277 officers. They are not coming from outside. They are the whole-time employees, assisting the CMD of the bank. There is only one CMD. They are going to assist him.

17.00 hrs.

To strengthen management similar provisions exist in public sector banks with comparable business. The growth has been such that this is a small size bank. Banks with a business of more than one lakh crore rupees need somebody to assist the CMD. That is why we have come before you for your approval and this is justified.

Shri Balkrishna Khanderao Shukla also raised a point that increasing capital from Rs.2000 crore to Rs.10000 crore is very risky. This proposal to increase the authorised capital is only an enabling provision. The actual capital will be infused by the Government based on growth in the business of the bank and to meet regulatory requirements of the RBI. As and when money is required, it will be infused through the Budget.

Many hon. Members have underlined the need to encourage export. Several Members have spoken about increasing the capital. That is why we have come before you to increase the capital. Increasing the capital and strengthening the management will help achieve the objective of export also.

Shri Vijay Bahadur Singh has raised the question of operational cost to be looked into. The administrative cost of the EXIM Bank is only 2.79 per cent of the total expenses in the year 2010-11, which is one of the lowest in the banking industry. There are only 277 persons working in the bank. So, the administrative cost is under control. He also raised the point as to how this monitoring mechanism is working in the EXIM Bank. The EXIM Bank has a Board to run it professionally. RBI inspects it periodically. Every year a statement of intent is finalised with the Government. It means the Board is overseeing, the RBI is monitoring and the Government is also monitoring the performance of the Bank against which the performance is measured. Annual Reports are also placed on the Table of the House for your perusal. Therefore, there is an in-built mechanism.

Shrimati Meena Singh, Shri Bhartruhari Mahtab and Dr. Raghuvansh Prasad Singh raised the question as to what is the bank doing for the benefit extended to small scale industries. To promote credit to SMEs, the Government fixes the target in respect of EXIM Bank. In the year 2010-11, a target of Rs.1160 crore was fixed, against which the EXIM Bank provided a credit of Rs.1196 crore. It was more than the target fixed. The credit flow to this sector was more than what was targeted.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL : What is the percentage of the total turn over?

SHRI NAMO NARAIN MEENA: What was the target fixed? The target fixed was Rs.1160 crore and they exceeded the target. It means they have achieved more than 100 per cent.

Many hon. Members have raised the point that area of operation should be diversified to other countries also. The EXIM Bank has extended the line of credit to promote India's export to developing countries and newer markets like Ethiopia, Sudan, Oman, Malaysia, Libya, UAE, Senegal, Tanzania, etc., for a variety of sectors such as infrastructure, industries, transportation, rural electrification, generation and transmission, etc.

Sir, the same question was asked by Shri S. Semmalai about the number of whole-time Directors. As I have already explained, there is only one whole-time Director; the other Directors are nominees. This is a small-size bank which is having business of more than Rs. 1,00,000 crore. So, two more persons are required. That is why, we have come to seek your approval.

A question was raised by Shri S. Semmalai, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, Shri Prem Das Rai and other hon. Members regarding the proviso that an open-ended provision may dilute the supremacy of Parliament and we should come again and again to Parliament for raising the capital. In this regard, I would like to tell two or three things. I have already told you that this is an enabling provision, but the authorised capital of a financial institution is a dynamic parameter, which has to be revised periodically keeping in view the growth of business volume, regulatory compliance and so on. Moreover, if there is a cap on the authorised capital, any further increase beyond the cap as necessitated would require amendment to the Act, which is a cumbersome and time-consuming process. Keeping this in view, it is prescribed in the proviso that the Central Government may be empowered to increase the authorised capital up to an amount, as it may deem necessary, through a notification which also be laid on the Table of the House.

Again, in any case, the capital infusion in the EXIM Bank is made through a budgetary provision and Plan schemes, which require specific approval of the Parliament. It means that the capital infusion will be through Budget. A provision will be made in the Budget that we would be capitalising the Bank, we would be giving so much of money for the business growth to EXIM Bank, and that will come before the House. That is why, this provision is there.

With these remarks, I commend the Bill for consideration of the House.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, this Bank is especially going to provide or is providing it as a facilitator for export and import trade. Invariably cutting across party lines, all of us have said that small-scale industries should be provided more facility and more credit. The Minister very well knows that 45 per cent of our export relates to small-scale industries and medium-scale industries, but the target that has been fixed by this Bank is hardly one per cent of its total turnover. I would like to get a reply from the hon. Minister whether the Government is going to fix a specific ratio of the turnover that they have to meet, a specific target of the turnover that they have to meet for the small-scale industries which are engaged in export and import as it is with all public sector banks for agriculture. We have a specific target for every bank in every district that it has to meet. Similarly, in EXIM Bank, are they going to fix a specific target instead of leaving it to the concerned bank? I want to know whether the Government is going to raise it because 45 per cent of our export is relating to small-scale industries.

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला : महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि एनपीए बहुत ही कम है। पिछले दो साल में एनपीए इन एमाउंट, नॉट इन परसेंटेज, एक तो यह बात है। दूसरा आपने कैपिंग बताया है कि दस हजार करोड़ से ऊपर जाने के लिए हम थ्रू बजट प्रोविजन करेंगे। मुझे लगता है कि यह बिल में कहीं लिखा नहीं गया है कि थ्रू बजट यह प्रोविजन होगा। बिल में लिखा गया है कि थ्रू आथोराइज दि बैंक रिव्यु जो करना है और जो बढ़ाना है, उसकी आथोरिटी भी

इसी बिल में सम्मिलित की गई है। मुझे लगता है कि बिल में यह कहीं संशोधित होना चाहिए कि थ्रू बजट करना है।

श्री नमोनारायन मीणा : महताब जी ने जो बताया, I agree with Mr. Mahtab that we need to improve the credit flow to the MSME sector. I have noted it as this is a policy matter. But about 2.6 per cent of the total lending during the year, was to MSME sector and the Bank has been achieving 100 per cent of whatever target was given to the bank.

As far as Mr. Shukla's question is concerned about capitalisation of the bank, it is depicted in the Budget. In any case, if some notification is to be issued, then it will be laid before the Parliament. So, there is no question of authorising the banks any other way.

MR. CHAIRMAN: The question is :

"That the Bill further to amend the Export-Import Bank of India Act, 1981, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and theLong Title were added to the Bill.

SHRI NAMO NARAIN MEENA : I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.